REACH Lilly MDR-TB Partnership Media Fellowship Programme

2012-13 FELLOW : MUKESH KEJARIWAL

Mukesh Kejariwal *has been covering health and developmental issues for both print and electronic media for almost a decade. He is presently with the National Bureau of Dainik Jagran, India's leading newspaper, as a Special Correspondent. Mukesh is well-known for his investigative reports which have uncovered scams as well as his critique of health issues, particularly at the policy level. He is active on social networking media and uses the Right to Information Act extensively in his reporting.*

राष्ट्रीयजागरण

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2013

दवा छूटी तो याद दिलाएगा मोबाइल

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

विशेष
दैनिक जागरण

क्षय से निर्भय

- देश के सारे टीबी मरीज चार महीने में होंगे सरकारी लाइन पर
- आठ लाख मरीजों का पूरा स्वास्थ्य रिकार्ड ऑनलाइन

सरकार का दावा है कि चार महीने के अंदर देश भर में टीबी के सभी मरीज मोबाइल के जरिये सीधे सरकारी लाइन पर होंगे। दवा की एक भी खुराक छूटते ही उन्हें तुरंत सूचना दी जा सकेगी। साथ ही सरकारी व्यवस्था पर निगरानी भी चाक-चौबंद हो सकेगी। अब तक आठ लाख मरीजों का आंकड़ा उनके पूरे ब्योरे के साथ ऑनलाइन किया जा चुका है।

केंद्र सरकार के संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के प्रमुख डॉ अशोक कुमार विश्वास जताते हैं कि जून तक सभी मरीजों का रिकार्ड इस पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एसएमएस और फोन से संपर्क किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। अपने एंड्रायड मोबाइल पर उपलब्ध इसकी नवीनतम रिपोर्ट देखकर वे बताते हैं कि अब तक 7,98,204 मरीजों का रिकार्ड इस पर दर्ज हो चुका है। हर रोज तीन से चार हजार मरीजों का आंकड़ा डाला जा रहा है। निगरानी की व्यवस्था ऐसी है कि किसी भी समय राष्ट्रीय स्तर पर वे इसकी पूरी रिपोर्ट अपने मोबाइल के जरिये ही देख सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की 'निक्षय' योजना के लिए तकनीकी सहायता केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) उपलब्ध करवा रहा है। कुमार बताते हैं कि टीबी दवा लेने में लापरवाही बेहद खतरनाक होती है। नई व्यवस्था के जरिये मरीज कुछ समय के लिए दूसरी जगह भी जाता है तो 13 अंकों के विशिष्ट नंबर के आधार पर बिना किसी रुकावट या फेरबदल के दवा और इलाज हासिल कर सकेगा। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन 'द यूनियन' में 'प्रोजेक्ट अक्षय' के संयोजक सुब्रम मोहंती इस बारे में पूछे जाने पर कहते हैं कि भारत में सात से आठ फीसद मरीज डाट्स इलाज बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे उपायों से यह संख्या काबू की जा सकती है।

पांच फायदे नई व्यवस्था के

1. हर नया मामला सीधे आला अधिकारियों की निगरानी में होगा
2. दवा की एक भी खुराक छूटते ही मरीज को दी जा सकेगी सूचना
3. राष्ट्रीय स्तर पर इलाज के प्रभाव का नियमित आकलन किया जा सकेगा
4. किसी भी इलाके में सरकारी ढांचे की लापरवाही भी तुरंत सामने आएगी
5. दवा आदि की उपलब्धता व वित्तीय प्रबंधन भी इसी प्लेटफार्म पर होगा

भारत में टीबी

- सबसे ज्यादा मरीज भारत में
- सालाना 22 लाख नए मामले
- हर तीन मिनट में होती है दो मौतें

दवा प्रतिरोधी टीबी मरीजों के लिए जिला अस्पतालों में अलग वार्ड

- दवा का असर खत्म होने के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बढ़ी सक्रियता

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

टीबी मरीजों को दी जाने वाली दवा के बेअसर होने के खतरे को देखते हुए अब जिला अस्पतालों में दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के लिए पूरी तरह से अलग वार्ड तेजी से बनाए जा रहे हैं। एक वर्ष के अंदर देश भर के 120 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दस या अधिक बिस्तरों के ऐसे वार्ड शुरू कर लिए जाएंगे, जहां ये मरीज किसी भी तरह दूसरे रोगियों के संपर्क में नहीं आ सकेंगे। इसी तरह दवा प्रतिरोध के गंभीर मामलों (एक्सडीआर) टीबी से निपटने के लिए भारत में नई दवाओं का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के प्रमुख डॉ. अशोक कुमार 'दैनिक जागरण' से बातचीत में दावा करते हैं कि अगले एक साल के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत पूरी करने के लिए औषधि प्रतिरोधी (डीआर) टीबी केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। इसके तहत 120 जिला अस्पताल या मेडिकल कालेज अस्पतालों की पहचान की गई है। यह दस बिस्तरों का आयसोलेशन वार्ड होगा, जहां सभी जांच और दवा सहित पूरा इलाज मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही इनमें संक्रमण के फैलाव को रोकने के पूरे इंतजाम भी होंगे। कुमार बताते हैं कि 'दवा प्रतिरोधी टीबी कार्यबद्ध प्रबंधन' (पीएमडीटी) के तहत अब तक देश भर में ऐसे 78 वार्ड शुरू कर लिए गए हैं। उधर, स्वास्थ्य मंत्रालय के ही मुताबिक भारत में टीबी की नई दवाओं का ट्रायल शुरू हो गया है। दवा प्रतिरोधी मरीजों के लिए विकसित की गई दवाओं बीडाक्वीलाइन, डेलामिनिड और पीए- 824 का चेन्नई स्थित राष्ट्रीय टीबी शोध संस्थान और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मरीजों पर ट्रायल चल रहा है।

चालीस पार वालों के लिए काला मोतियाबिंद जांच जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालीस साल से ऊपर की उम्र वालों को हर साल काला मोतियाबिंद की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि कई बार यह बिना मरीज को कोई तकलीफ दिए ही बहुत खतरनाक स्तर तक आंखों की रोशनी को नष्ट कर देता है। रविवार से शुरू विश्व काला मोतियाबिंद सप्ताह के दौरान विशेषज्ञों ने यह सलाह दी है। पद्म श्री सम्मानित प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक ग्रोवर बताते हैं कि काला मोतियाबिंद इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे हुए नुकसान को किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। समय पर पता लगा कर इसके नुकसान को रोका जरूर जा सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि इसकी सालाना जांच करवाई जाए।

REACH

SPEAK UP TO STOP TB

the Lilly MDR-TB partnership